

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com



हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोन:- 230200, 230400 फॅक्स:- 07469-230600

वर्ष: 17

संख्या: 308

प्रभात

हिण्डौन सिटी, मंगलवार 8 सितम्बर, 2026

पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18

पृष्ठ 8

मूल्य 2.50 रु.

जर्मनी के चुनाव में ‘‘नैशनलिज़्म’’ की पुरजोर ढंग से वापसी ने सभी को चौंका दिया है

अब तक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जर्मनी की राजनीति यहूदियों पर हुए अत्याचार से उत्पन्न देशव्यापी ग्लानि पर आधारित रहती थी

–अंजन राॅय–

–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, 7 सितम्बर। क्या इतिहास, यानी किसी समुदाय की सामूहिक याद के तौर पर, आज के चुनाव में कोई भूमिका निभाता है? हां, जर्मनी में पिछले रविवार हुए एक महत्वपूर्ण चुनाव के नतीजों को देखकर ऐसा कहा जा सकता है।

एक कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, यानी एएफडी ने देश के एक राज्य में हुए चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस जीत से पूरे यूरोपीय संघ में चिंता की लहर दौड़ गई है और रूस में खुशी की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इसकी लहरें अटलांटिक पर अमेरिका तक पहुंच गई हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चुनाव के नतीजों का जिक्र किया है।

यूरोप हैरान है और इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि क्या

■ पर, वर्तमान चुनाव में राजनीति का आधार ग्लानि को पीछे छोड़कर जर्मनी के अन्य समृद्ध इतिहास की ओर मुड़ा है।

■ ऐसा लग रहा है, हिटलर की ज्यादातियों की याददाश्त को धूमिल कर जर्मनवासी बिस्मार्क की ओर देख रहे हैं।

■ इस मानसिक बदलाव में, जर्मनीवासी अपने देश को ‘‘एक विचारकों व कवियों’’ के देश के रूप में जानना व याद रखना चाहता हैं।

■ चाहे, आधुनिक जर्मनी, अधिक समृद्ध है। पर, नई पीढ़ी शायद कुछ कम समृद्धि बर्दाश्त करने को तैयार है, पर, अपनी ‘‘जर्मननेस’’ (जर्मन्स) को बरकरार रखने में ज्यादा खुशी महसूस करना चाहती है।

यह जर्मन राष्ट्रवाद के फिर से उभरने की एक छोटी सी शुरुआत है। हो सकता है कि नाज़ी दौर के अनुभव के कारण यूरोप अब भी एक तरह की मानसिक बेचैनी

से गुजर रहा हो।

एएफडी ने रविवार को अपने सबसे नए प्रतिद्वंद्वी कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी, यानी सीडीयू

पर जोरदार चुनावी जीत हासिल की है, जो अपने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पार्टनर, एसपीडी के साथ गठबंधन में फ़ेडरल लैबल पर शासन करती है।

एएफडी जर्मनी को हिटलर के जर्मनी के बजाय, ओटो फॉन बिस्मार्क के जर्मनी के तौर पर देखने को बढ़ावा दे रही है। वह उन्नीसवीं सदी के जर्मनी और जर्मनी एकता के इतिहास को पढ़ाने की बात कर रही है, जिसमें हिटलर के शासन और राष्ट्रीय समाजवाद, उत्पीड़न और युद्ध की किसी भी गलती को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।

बिस्मार्क ने अनेक छोटे राज्यों और रियासतों को एकजुट करके उस देश की नौव रखी, जो बाद में बीसवीं सदी में जर्मनी बना। पार्टी ‘‘ज्यादा बिस्मार्क और कम हिटलर’’ की बात कर रही है।

नाज़ी शासन को उसके अत्याचारों से बरी नहीं करते हुए, एएफडी उन लोगों की भावनाओं को सामने रख रही है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुए हैं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सत्य निकेतन हादसा, बिल्डिंग की मालकिन, पति व पुत्र गिरफ्तार

नई दिल्ली, 07 सितंबर। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत ढ हने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान मालिक के परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संपत्ति की मालकिन उर्मिला गुप्ता (75), उनके पति हरिराम गुप्ता (81) और बेटे महेश

■ हादसे में जान गंवाने वाले 7 लोगों में 6 युवक थे।

गुप्ता (52) को गिरफ्तार किया है। हादसे के बाद चलाए गए लंबे बचाव अभियान में मलबे के नीचे दबे कुल 12 लोगों को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से सात लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच घायल अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में जान गंवाने वालों में ज्यादातर युवा छात्र थे।

सरकार को अविलंब आना पड़ा, इसरो के स्टाफ की आशंका दूर करने के लिए

स्टाफ में आशंका का कारण था, ‘‘इन-स्पेस’’ के अध्यक्ष पवन गोयंका का वह वक्तव्य जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘‘इसरो अब कोई लॉन्च व्हिकल्स’’ नहीं बनाएगा। यह सारा काम अब प्राइवेट सैक्टर व प्राइवेट पार्टियों के लिए छोड़ दिया जाएगा

–डॉ. सतीश मिश्रा–

–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, 7 सितम्बर। मोदी सरकार ने देश की अंतरिक्ष एजेंसी ‘‘इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो)’’ के काम के तेजी से हो रहे निजीकरण को लेकर उसके कर्मचारियों के बढ़ते हुये डर, बेचैनी और चिंता को शुरू में ही खत्म करने की कोशिश की है। कुछ निजी कंपनियों को काम करने के लिए लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने इसरो से एक बयान

जारी करने को कहा, जिसमें कहा जाए कि इसरो देश की प्रमुख अंतरिक्ष संस्था बनी रहेगी। यह कदम इसरो के कर्मचारी संगठनों द्वारा इसरो कुछ गतिविधियों को निजी और सरकारी कंपनियों को सौंपने की योजनाओं पर चिंता जताए जाने के बाद उठाया गया। केन्द्र सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब विपक्ष मोदी सरकार को संवेदनशील और रणनीतिक तकनीकों को निजी क्षेत्र को सौंपने की योजना का विरोध कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने इसरो के कथित निजीकरण को तुरंत

■ पवन गोयंका का इशारा था कि इसरो अब भविष्य में स्पेश रिसर्च व नई-नई टेक्नॉलजी विकसित करने की आर एण्ड डी का ही काम करेगा।

रोकने की मांग की है।

विपक्ष का विरोध ‘‘आईएन-स्पेस’’ के अध्यक्ष पवन गोयनका के उस बयान के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘‘आखिरकार इसरो कोई भी प्रक्षेपण यान न तो बनाएगा और न ही उसका निर्माण करेगा’’ और इसका पूरा उत्पादन सरकारी उपक्रमों या निजी कंपनियों को पूरी तरह सौंप

दिया जाएगा।

गोयनका के इस बयान के बाद, इसरो के नौ कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त रूप से विरोध पत्र जारी किया। भारत अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी दुनिया के प्रमुख देशों में से एक है।

इसरो ने मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान भेजा है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के

पास यान उतारा है और अपना खुद का प्रक्षेपण तंत्र यान विकसित किया है। वह देश की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान की भी तैयारी कर रहा है।

एजेंसी ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘इसरो उन्नत अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीक के विकास, राष्ट्रीय और रणनीतिक अभियानों, अंतरिक्ष विज्ञान और खोज तथा अंतरिक्ष की महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक क्षमताओं के लिए भारत का प्रमुख संस्थान बना रहेगा।

इस पोस्ट में उन आशंकाओं को दूर करने की भी कोशिश की गई कि

संगठन का न तो निजीकरण किया जाएगा और न इसका महत्व ही कम किया जाएगा।

यह बयान 4 सितंबर को कर्मचारी संगठन के उस पत्र के बाद आया, जिसे मीडिया ने प्रकाशित किया था और ‘‘रॉयटर्स’’ ने भी देखा था। इसमें इसरो के कुछ कर्मचारियों ने इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन से उन खबरों पर स्पष्टीकरण मांगा था, जिनमें कहा गया था कि वर्तमान में एजेंसी द्वारा संचाली जा रही निर्माण और संचालन की जिम्मेदारियां कंपनियों को सौंप दी जाएंगी।

नई दिल्ली, 07 सितंबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह जंतर-मंतर पर आरक्षण और यूजीसी के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाजत देने पर 14 सितंबर तक फैसला ले। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने ये आदेश दिया। क्षत्रिय करणी सेना 20 सितंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है। कोर्ट ने क्षत्रिय करणी सेना से कहा है कि वह पुलिस को अपना आवेदन दे। पुलिस 14 सितंबर तक उस पर फैसला करेगी और आपको अपने फैसले की जानकारी देगी।

छह विधानसभा व एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव 6 अक्टूबर को

नई दिल्ली, 07 सितंबर। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की पांच विधानसभा सीटों तथा असम की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन छह सीटों पर मतदान छह अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना नौ अक्टूबर को की

■ मतगणना 9 अक्टूबर को होगी।

जाएगी। चुनाव प्रक्रिया 11 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी।

आयोग के अनुसार, तमिलनाडु की मदुरांतकम (अनुसूचित जाति) और धारापुरम (अनुसूचित जाति) विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। पुदुचेरी की थट्टानचावडी विधानसभा सीट तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर भी मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। इन सभी सीटों पर रिक्तियां संबंधित निर्वाचित सदस्यों के इस्तीफे के कारण हुई हैं।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार चुनाव की अधिसूचना नौ सितंबर को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 19 सितंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। मतदान छह अक्टूबर और मतगणना नौ अक्टूबर को होगी।

राहुल की यात्रा से पूर्व पायलट को पंजाब की खेमेबाजी का समाधान निकालना है

जिम्मेवारी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि, राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मु.मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ, एक बड़े खेमे का नेतृत्व कर रहे हैं

–जाल खंबाता–

–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–

नई दिल्ली, 7 सितम्बर। पंजाब कांग्रेस में हुए फेरबदल ने पार्टी की प्रदेश इकाई को न केवल हैरान किया है, बल्कि यह स्पष्ट संदेश भी दिया है कि केन्द्रीय नेतृत्व के पास जानकारी हासिल करने की अपनी निजी व्यवस्था भी है और वह किसी एक व्यक्ति की राय पर निर्भर नहीं है।

कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश बघेल को पंजाब भेजा था, तथा उन्हें गुटों में बँटी प्रदेश कांग्रेस को एकजुट करने की विशेष जिम्मेदारी दी गई थी। अब बघेल को पंजाब से हटा दिया गया है और उनकी जगह सचिन पायलट को यह जिम्मेदारी दी गई है।

पंजाब के नये प्रभारी सचिन

■ साथ ही यह भी विदित है कि राजस्थान के प्रभारी के रूप में रंधावा को गहलोत समर्थक माना जाता है।

पायलट ने राजस्थान में भी इसी तरह की गुटबाजी का सामना किया है और वे अच्छी तरह समझते हैं कि इससे पार्टी को कितना नुकसान होता है।

एक खास दिलचस्प बात यह है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो इस समय चन्नी खेमे में एक प्रमुख नेता हैं, पायलट के गृह राज्य राजस्थान के प्रभारी हैं।

अब पायलट की जिम्मेदारी होगी कि वे रंधावा को चन्नी खेमे से अलग करके अपने साथ लाएं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पंजाब के सभी गुटों में पायलट को स्वीकार किया जाता है और हाईकमान के इस फैसले का पार्टी

नेताओं तथा कार्यकर्ताओं, दोनों ने स्वागत किया है।

अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पायलट के सामने, राहुल गांधी के पंजाब दौरे से पहले, सभी नेताओं को एकजुट करने की चुनौती है, ताकि एकता का माहौल बनाया जा सके और जनता को यह संदेश दिया जा सके कि अंदरूनी बदलावों के बाद ‘‘सब चंगा सी’’, यानी सब कुछ ठीक है।

फिलहाल एक गुट का नेतृत्व चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा कर रहे हैं, जबकि विधानसभा में

नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग अपने-अपने अलग गुटों का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, राजा वर्डिंग को जिला अध्यक्षों का भी समर्थन हासिल है, क्योंकि उन्हीं ने उनकी नियुक्तियों की थी।

प्रभारी के रूप में बघेल से उम्मीद की गई थी कि वे इन गुटों को एक साथ लाकर पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन वह इस काम में सफल नहीं हो सके और उन पर आरोप लगा कि वे खुद ही एक अलग गुट बन गए थे।

कांग्रेस हाईकमान को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में बघेल ने यथास्थिति बनाए रखने की सिफारिश की थी और, खास तौर पर, राजा वर्डिंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बनाए रखने की बात कही थी।

दिल्ली में संगठन प्रभारी के साथ हुई बैठक में, चन्नी और रंधावा ने वर्डिंग को हटाने की मांग की थी। इस बीच, राहुल गांधी के पंजाब के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुलिस जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति पर 14 तक फैसला ले- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 07 सितंबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह जंतर-मंतर पर आरक्षण और यूजीसी के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाजत देने पर 14 सितंबर तक फैसला ले। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने ये आदेश दिया। क्षत्रिय करणी सेना 20 सितंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है। कोर्ट ने क्षत्रिय करणी सेना से कहा है कि वह पुलिस को अपना आवेदन दे। पुलिस 14 सितंबर तक उस पर फैसला करेगी और आपको अपने फैसले की जानकारी देगी।

CM / K

⊕

⊕

⊕

CM / K